

रजिस्टर्ड नं० एल०-३३/एस०एम०/१३-१४/९६.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बोरवार, ११ जुलाई, १९९६/२० आषाढ़, १९१८

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खंड)

अधिसूचना

शिमला-२, २७ मई, १९९६

संख्या एल० एल० आर० (राजभाषा) बी० (१६)-४/९६. — स्यूटस वैल्यूएशन (हिमाचल प्रदेश ग्रामैन्डमेंट) ऐक्ट, १९६९ (१९६९ का ३०) के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तारीख १४-५-९६

के प्राधिकार के अधीन एतद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विश्वि) ।

वाद मूल्यांकन (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1969

(1969 का 30)

(23 दिसम्बर, 1969 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित)

(30-4-96 को यथाविद्यमान)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाद मूल्यांकन (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1969 है ।

संक्षिप्त
नाम और
विस्तार ।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

2. हिमाचल प्रदेश में यथा लागू वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 (1887 का केन्द्रीय अधिनियम 7) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और धारा 8 तथा धारा 9 में "न्यायालय फीस अधिनियम, 1870" पद के स्थान पर, जहाँ वह आता है "हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968" पद, रखा जाएगा ।

धारा 3, 8
और 9 का
संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में "न्यायालय फीस अधिनियम, 1870, धारा 7, पैरा (iv) या अनुसूची 2, अनुच्छेद 17" पद के स्थान पर "हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968, धारा 7, पैरा (iv) या अनुसूची 2, अनुच्छेद 13 या 18" पद रखा जाएगा ।

धारा 4 का
संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

धारा-11(1)
में परन्तुक
का जोड़ा
जाना ।

"परन्तु लेखा के लिए वाद में, विचारण की किसी अवस्था में अधिकारिता के प्रयोजन के लिए न्यायालय द्वारा यथा अवधारित मूल्य, अन्तिम और निश्चायक होगा और अपील या पुनरीक्षण में उसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकेगा ।"

1966 का 31 5. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में
1938 का 1 जोड़े गए क्षेत्रों के यथा प्रवृत्त दि स्पूट वैल्यूएशन (पंजाब अमैन्डमेंट) ऐक्ट, 1938
1942 का 13 और दि स्पूट वैल्यूएशन (पंजाब अमैन्डमेंट) ऐक्ट, 1942 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

निरसन और
व्यावृत्तियां ।

परन्तु तद्धीन की गई कोई बात या कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

